

संक्षिप्त समाचार

मां की शर्मनाक करतूत, बेटी को देती संबंध बनाने की ट्रेनिंग, करती थी ये दावा

नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया है। जहाँ, एक माँ अपनी बच्ची का यौन उत्पीड़न करती रही। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसकी मां, उसे सेक्स करने की ट्रेनिंग देती है। छात्रा ने बताया कि उसकी मां कहती हैं कि यह ट्रेनिंग शादी के बाद पति के साथ संबंध बनाने में काम आएगी। हालाँकि महिला अपने बेटी के इन आरोपों से इनकार किया है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक यह छात्रा नॉर्थ बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। वह अपनी 45 वर्षीय माँ और बड़ी बहन के साथ रहती है। मां से मतभेद के चलते छात्रा के पिता परिवार से अलग रहते हैं। छात्रा का कहना है कि उसके साथ यह सिलसिला पिछले एक साल से चल रहा है। पुलिस ने अभी घटना के बारे में पीड़ित छात्रा का बयान नहीं दर्ज किया है। वहीं, छात्रा की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उसने आरोपों से इनकार किया है।

अब आसमान से होगी दुश्मनों पर नज़र! भारत लॉन्च करेगा 52 सैटेलाइट

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। देश एक या दो नहीं, बल्कि 52 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। ये सभी सैटेलाइट विशेष रूप से सेना के लिए काम करेंगी, जिससे पाकिस्तान समेत दुश्मन देशों के हर कोने पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, सेना के लिए एक विशेष स्पेस डॉकिंग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चल रही है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने सैटेलाइट सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों की सफलतापूर्वक निगरानी की थी, जिससे सेना को सटीक निशाना साधने में काफी मदद मिली थी। भारत द्वारा यह सैटेलाइट लॉन्च ‘स्पेस बेस्ट सर्विलांस प्रोग्राम’ (एसबीएस) के तीसरे चरण का हिस्सा है। इस कार्यक्रम को पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी।

पुलिस की दबंगई : एसएचओ के थप्पड़ जड़ते ही दुकानदार हुआ बेहोश

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले के कैथूनीपोल इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसोवाल पर एक दुकानदार रिजवान के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। यह घटना 29 मई 2025 को हुई, जब सड़क पर खड़ी एक मोटरसाइकिल को हटाने को लेकर विवाद हो गया। इस मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित रिजवान एक अलमारी बनाने की दुकान पर काम करता है।

नई खेल नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

2047 तक भारत को शीर्ष-पांच खेल राष्ट्र बनाना लक्ष्य

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार (01 जुलाई, 2025) को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, खेल से जुड़ी खेलो भारत नीति, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे को चार लेन का बनाने के लिए मंजूरी दी। कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में

देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसका कुल बजट: 99,446 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 की जगह लेती है, साथ ही भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप पेश करती है।



भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार

(आरडीआई) योजना को मंजूरी दे दी है। आरडीआई योजना का उद्देश्य आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त

प्रदान करना है। यह योजना निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है और नवाचार को सुविधाजनक बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को विकास और जोखिम पूंजी प्रदान करने का प्रयास करती है। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजूरी दी। खंड की कुल लंबाई 46.7 किमी है और परियोजना लागत 1,853 करोड़ रुपये है। दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

शोध और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़

सरकार ने देश में शोध, नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट ने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्क्रीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश में शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन वाली योजना को तैयार करने से पहले अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फंडेशन (इन्फ्रस्ट्र) ने दुनिया के कई देशों के सफल शोध मॉडलों का अध्ययन किया। इनमें अमेरिका, इजरायल, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों के मॉडल शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम

पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू की....

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 75 साल के इतिहास में पहली बार स्टाफके लिए आरक्षण नीति लागू की है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नीति 23 जून 2025 को लागू हुई। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कामकाज में बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि जजों पर आरक्षण लागू नहीं होगा और सिर्फ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ



निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट सहायक, चैंबर अटेंडेंट आदि पदों पर आरक्षण लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आपराधिक कानून पर बोले शाह

देश में कही भी हो एफआईआर 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा..

नई दिल्ली/ एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे। आज इन तीन नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि इस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन में अधिकतम तीन वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या न्याय प्राप्त करने



के लिए समयसीमा का अभाव है। शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज करें, आपकी 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा। बीएनएस, बीएनएसएस

एंटी-एजिंग दवाएं बर्नी मौत की वजह शेफाली जरीवाला केस में बड़ा खुलासा

मुंबई । अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में पुलिस जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारीयां सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि शेफाली पिछले सात से आठ सालों से नियमित रूप से एंटी-एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थीं। 27 जून को उनके घर में पूजा का आयोजन था, जिसके कारण शेफाली व्रत पर थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसी दिन दोपहर में एंटी-एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। यह दवाएं उन्हें वर्षों पहले एक डॉक्टर की सलाह पर दी गई थीं, और तब से वह हर महीने यह ट्रीटमेंट लेती आ रही थीं। पुलिस को इस बात का संदेह है कि उनकी अचानक मृत्यु का एक बड़ा कारण यह दवाएं भी हो सकती हैं।

एंटी-एजिंग दवाएं बर्नी मौत की वजह शेफाली जरीवाला केस में बड़ा खुलासा

हिमाचल में मानसून का कहर!

बारिश-भूस्खलन के कारण 250 सड़कें बंद,मंडी में बादल फटा

नई दिल्ली/ एजेंसी

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भारतीय मौसम विभाग ने भूस्खलन की चेतावनी जारी की। राज्य के 22 में से 18 स्थान चेतावनी के दायरे में आते हैं और वर्तमान में भूस्खलन के खतरे में हैं। लगातार हो रही बारिश ने लगभग 130 क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित कर दी है और पूरे राज्य में पानी की आपूर्ति को प्रभावित किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य भर में 250 से अधिक सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसमें सबसे अधिक नुकसान सिरमौर और मंडी जिलों में हुआ है, जहां क्रमशः 57 और 44 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इस बीच, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और

सोलन जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को 30 जून को स्कूलों को बंद करने का आदेश देने का निर्देश दिया है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला-कालका रेल लाइन पर भी रात भर हुई बारिश के बाद पटरियों से मलबा और पेड़ हटाए जाने तक सेवाएं घंटों तक स्थगित रहें, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। पूरे राज्य में बारिश से संबंधित कई घटनाएं भी सामने आईं, जिसके कारण पिछले 24 घंटों में तीन लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मानसून की शुरुआत से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 20 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने और भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में एक व्यक्ति की



मौत हो गई और करीब 12 लोग लापता हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंडी में सोमवार शाम से 216.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एक व्यक्ति की मौत

हो गई है, जबकि 12 से 13 लोग लापता हैं। करसोग में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि मंडी के स्याज में दो परिवारों के करीब सात लोग लापता हैं। देवगन ने बताया कि भारी बारिश के बाद बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से

जिले में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने की सूचना है। करसोग के पुराना बाजार (पंजरत), कुट्टी, बराल, ममेल और भ्याल गांवों में सड़कें और वाहन बह गए हैं। मंडी की लौंगनी पंचायत के स्याठी गांव में भारी बारिश के कारण कई घर, गौशालाएं, घोड़े, मवेशी और बकरियां बह गई हैं, जबकि पंडोह के पास पट्टीकरी बिजली परियोजना में निवासियों के घरों में पानी घुस गया है। जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं और ब्यास नदी पर बने पंडोह बांध से डेढ़ लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। पंडोह बांध का जलस्तर खतरे के निशान 2,922 फुट के मुकाबले 2,941 फुट तक पहुंच गया है।

अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता,भगवान शिव की प्रतिमा डूबी

रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ाई हुई। यहां स्थित छोटें मंदिर और भगवान शिव की प्रतिमा डूब गई है। बढ़ते जलस्तर को देख श्रद्धालुओं को चिंता सताने लगी है। सोमवार सुबह से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू हुई। पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अपराह्न 3 बजे तक कुल 7936 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया, जिसमें देर शाम तक ज्यादातर धाम पहुंच चुके थे। वहीं, बाबा केदार के दर्शन कर 8400 श्रद्धालु सकुशल सोमप्रयाग पहुंचे। मौसम के पूर्वानुमान के चलते शासन स्तर से सोमवार को चारधाम यात्रा को बंद करने का निर्णय लिया गया था। वहीं, सोमवार को सुबह 8 बजे गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा बंद के आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को मौसम के हिसाब से यात्रा संचालन के निर्देश दिये।



संपादकीय

अंतरिक्ष अब कुतूहल का विषय नहीं, बल्कि कारोबारी संभावनाओं के अनंत आकाश में तब्दील हो चुका है। इसीलिए दुनिया के तमाम उन्नत देश अंतरिक्ष में अपनी पहचान अंकित करने की होड़ में नजर आते हैं। भारत भी पिछले कुछ वर्षों से अपने तकनीकी विकास, अनुसंधान क्षमता और प्रणाली के बल पर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों की कतार में शामिल हो गया है। उपग्रह प्रक्षेपण के कारोबार में तो वह दुनिया के कई देशों को चुनौती देने लगा है। अब भारत अपनी

शुभांशु की उड़ान से गगनयान को मिला नया आत्मविश्वास

महत्वाकांक्षी गंगानयन योजना पर काम कर रहा है। उस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा ने एक्सप्लोर मिशन-4 के तहत तीन चार अंतरिक्ष यानों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है, उनमें भारतीय वायुसेना के कप्तान शुभांशु शुक्ल भी शामिल हैं। शुभांशु को खासतौर पर गंगानयन मिशन की दृष्टि से ही तैयार किया गया था। वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँच कर सात प्रयोग करेंगे। यह भारत के लिए एक्सप्लोर भी बड़ी उपलब्धि है कि हमें समर्थता देकर उसका तैयार किया हुआ

कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु को दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री का गौरव पाना हुआ है। अंतरिक्ष में मानव को भेजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्नत अंतरिक्ष यानों, ताकतवर कैमरों, रोबोटिक्स और आदि के विकास के बावजूद अंतरिक्ष के विस्तार को पूरी तरह खंगाल पाना संभव नहीं है। इसलिए अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया गया, ताकि वहां रह कर अंतरिक्ष यात्री विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर सकें। मगर उस स्टेशन तक मानव को भेजना और वापस लाना अब भी बड़ी चुनौती है। सुनीता

नविलियम्स के वहां लंबे समय तक फंस जाने की घटना से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हैजिन यात्रियों को वहां भेजा जाता है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए जिस तरह शरीर को ढालने की जरूरत होती है, वह कम ही लोग कर पाते हैं। फिर, उस स्टेशन तक यात्रियों को भेजने के लिए भरोसेमंद यान अभी तक अमेरिका ही विकसित कर पाया है। शुभांशु के अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने से भारत को अंतराष्ट्रीय यात्री तैयार करने का

रस्ता खुलेगा और गगनयान मिशन के लिए काम करने में काफी मदद मिलेगी। अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। उसका अध्ययन केवल इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें जीवन की संभावनाओं की तलाश हो सकेगी। विभिन्न ग्रहों पर खनिजों और नए तत्वों की खोज से विज्ञान व मानवता के लिए नए सारे भी खुल सकेगा। भविष्य में धरती के कई खनिज बढ़ती जरूरतों के आगे अपर्याप्त पड़ सकते हैं। इसीलिए दूसरे ग्रहों पर उनकी तलाश अभी शुरू की करनी पड़ेगी। फिर, अब तो अंतरिक्ष पर्यटन पर जोर बढ़ रहा है। इस दिशा में कई सरकारी व निजी ध्यास हो रहे हैं। गगनयान मिशन को भी इसी दृष्टि से विकसित किया जा रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं को भी ध्यान में ला सकें। ऐसे में शुभांशु जैसे अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत बढ़ेगी।

जल संरक्षण का जन आंदोलन बना जल गंगा संवर्धन अभियान



डॉ. मोहन यादव

क्षिति, जल, पावक, गगन,
समीरा, पंचतत्व से बना शरीर

रामचरित मानस की इस चौपाई के पंचतलों में से एक जल, जीवन का आधार है। हमें जीवन का अस्तित्व देने वाले को संरक्षित करना ही होगा। इसे आज वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है। ऋग्वेद की ऋचाओं में जल के महत्व, विशेषताओं और संरक्षण का संकेत है। रामायण और महाभारत में प्रकृति के संरक्षण का उल्लेख है। जल संरक्षण हमारी पुरातन संस्कृति है। यह अपनी परंपरा और संस्कारों की ऐतिहासिक विरासत है, जिसे हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है।

विकास की दृष्टि समग्र कल्याण के लिए है, जो प्रकृति संवर्धन से लेकर विकास के हर पक्ष में समाहित है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लंबे समय तक जल संरक्षण का अभियान चलाया था उन्हीं से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश में हमने जल गांधी संवर्धन अभियान की संकल्पना की। इस अभियान का शुभारंभ 30 मार्च गुड़ी पड़वा, नववर्ष विक्रम संवत् अवसर पर महाकाल की नगरी उज्जयिनी के शिप्रा तट से किया गया। यह अभियान जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन-जागरूकता को समर्पित रहा है। जल संग्रह के कई कीर्तिमान रचने के साथ आज हम जल संरक्षण की समृद्धि का उत्सव मना रहे हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस 90 दिन तक चले अभियान में पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जल-संरचनाओं पर काम हुआ है। अभियान में खंडवा जिले ने 1.29 लाख संरचनाओं का निर्माण किया है। इस विशेष उपलब्धि के लिए खंडवा को भू-गर्भ जल भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल सुरक्षा और प्रभावित जल प्रबंधन के लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया। इसी से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वर्षा की एक-एक बूंद को सहेजने का प्रयास किया गया। प्रदेश में पहली बार वर्षा जल को सहेजने का

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विरासत से विकास की दृष्टि समग्र कल्याण के लिए है, जो प्रकृति संवर्धन से लेकर विकास के हर पक्ष में समाहित है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लंबे समय तक जल संरक्षण का अभियान चलाया था उन्हीं से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश में हमने जल गंगा संवर्धन अभियान की संकल्पना की। इस अभियान का शुभारंभ 30 मार्च गुड़ी पड़वा, नववर्ष विक्रम संवत् अवसर पर महाकाल की नगरी उज्जयिनी के शिप्रा तट से किया गया। यह अभियान जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन-जागरूकता को समर्पित रहा है।

बड़े स्तर पर अभियान चला इससे भविष्य में भू-जल की निर्भरता कम होगी और पानी की हर बूंद का उपयोग होगा।

हमने प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ मित्र को आत्मसात किया और अपनी जीवन शैली में बदलाव कर पर्यावरण रक्षा का सूत्र हाथ में लिया है। इससे जन-जन में सूच्यवर्ण मित्र के रूप में जीवन जीने की परंपरा निर्मित हुई है। प्रदेशवासी मिशन लाइफ के अनुसार प्रकृति के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में पहली बार री-यूज वाटर पोर्टल निर्मित किया जा रहा है। यह पहल प्रदेश में जल संरक्षण और सूच्य उपयोग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह प्रदेश जल प्रबंधन के लिए तीन सिद्धांत री-यूज, रीड्यूज और री-साइकल पर आधारित रणनीति बनाकर काम कर रहा है।

यह हमारा सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश की धरती प्रकृति की विपुल सम्पदा से समृद्ध है। यह माँ नर्मदा, लिपुलेख, ताप्ती और बेतवा सहित लगभग 267 नदियों का मायाका है। प्रदेश में पहली बार नदियों को निर्मल और अविरल बनाने के लिए 145 से अधिक नदियों के उद्गम को चिह्नित किया गया और साफ-सफाई के साथ पौधरोपण की शुरुआत हुई है। नदियों के तट पर पौधरोपण की यह पहल नदियों को उनके मायके में हरि चुनरी ओढ़ाने का प्रयास है। प्रदेश में पहली बार जल संरक्षण के साथ जल समृद्धि की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की पहल की गई। इसके तहत राजाभोज ने बसाये भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर बड़े बाग की बावड़ी को सहेजने और पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस अभियान के अंतर्गत हमने 200 वर्ष पहले लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाई गई होलकर कालीन बावड़ी को जीर्णोद्धार उपरांत नया स्वरूप प्रदान किया है। इस बावड़ी का लोकर्पण करते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि हम माता अहिल्या के लोक कल्याण के युग में पहुँच गये हैं। बावड़ियाँ हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर

हैं, इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिये प्रदेश भर में दो हजार से अधिक बावड़ियों को पुनर्जीवित करते हुए बावड़ी उत्सव मनाया गया।

प्रधानमंत्री जी ने हमारी युवा शक्ति का जल सैनिक बनाने का आह्वान किया था। इस अभियान में, मध्यप्रदेश में पहली बार 2 लाख 30 हजार जल दूत बनाये गये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पानी बचाने के लिए यह अमृत मित्र भविष्य में जल सुरक्षा के अग्रदूत बनेंगे। प्रदेश में पहली बार डेढ़ लाख से अधिक कृषकों ने सभी विकासखंडों में 812 पानी चौपाल का आयोजन किया। इसमें किसानों ने अपने गांव के खेतों, जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर विचार-विमर्श किया।

प्रदेश में पहली बार खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए खेत तालाबों का चयन सिंपरी सॉफ्टवेयर से किया गया। अभियान में 83 हजार से अधिक बनने वाले खेत-तालाबों से प्रदेश के अस्वच्छता में नई उम्मीद जागी है। अब वे अपने खेत में एक नहीं कई फसलें ले सकते हैं। खेत तालाब के अलावा अमृत सरोवर और डागल रिचार्ज बनाने में भी सिंपरी सॉफ्टवेयर, एआई और प्लानर सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक से निर्धारित लक्ष्य को समय रहते प्राप्त करने में आसानी हुई है और गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए डेशबोर्ड डाटा को एआई के माध्यम से उपयोग से अभियान की प्रगति में सुधार और गति दी गई।

इस अभियान में प्रदेश के नगर-नगर और गांव-गांव में जल स्रोतों को शुद्ध और उपयोगी बनाने का कार्य चला, अनेक पोखर और बावड़ियों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। यह सरकार और समाज का संयुक्त प्रयास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पानी की बूंद-बूंद सहेजने का जो प्रयत्न किया गया है वह हमारे किसान भाइयों के लिए भारस पदार्थ का काम करेगा। सूखे खेत हरे-भरे होंगे, सुनहरी फसलें लहलहायेंगी। हमारा

किसान समृद्ध होगा और मध्यप्रदेश की धरती समृद्ध होगी।

वर्षा के जल को संग्रहित करने और पुराने जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए चलाए गए अभियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार रहा जनभागीदारी। सरकार, शासन-प्रशासन, समाजसेवी और प्रदेश के आमजन ने इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद आम पैयथोरोपण का व्यापक अभियान चलाया जायेगा।

मुझे खुशी है कि जल गंगा संवर्धन अभियान शासन के साथ जनता के लिए, जनता का अभियान बन गया है। इस अभियान ने जनआंदोलन का स्वरूप ले लिया है। प्रदेश ने यह प्रमाणित किया है कि यदि सरकार और जनता मिलकर कार्य करें तो कौं भी लक्ष्य असंभव नहीं। किसान, महिला, युवा और विद्यार्थियों ने जल संरक्षण को जीवन का मंत्र बना लिया है। इससे समाज में जल संरक्षण का भाव और भागीदारी का मानस विकसित हुआ है। इस अभियान ने हम सभी के मन को एक नये संकल्प और ऊर्जा से भर दिया है। यह अभियान केवल जल संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भविष्य की सुरक्षा का वह सूत्र है, जिससे प्रदेश की समृद्धि जुड़ी है।

÷अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति
चा÷

महाभारत के शांति पर्व का यह श्लोक जल के महत्व और जीवन में इसकी भूमिका का दर्शाता है। मैं प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता से पानी की बूंद-बूंद बचाने और जल समृद्ध राज्य बनाने का आह्वान करता हूँ।

आइयं, हम सब मिलकर पानी का हर बूँद बचाने का संकल्प लें, जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ायें। मुझे उम्मीद है कि जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश में जल की प्रचुर उपलब्धता और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

(लेखक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

बाढ़जनित हादसों में कब तक होती रहेगी जन-धन की हानि

देश में सरकारी मशीनरी की तंद्रा तब भंग होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र जागने के लिए बड़े हादसे की इंतजार में रहता है। पहले हुए हादसों से सबक सीखने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है जिम्मेदारी का अभाव। यदि यह जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसी तरह के हादसे के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हादसा होने की सूरत में उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तभी हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरुआत है।

(योगेंद्र योगी)

भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह अंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था।

देश में सरकारी मशीनों की तद्दा त्व बग हाती है, कज काई बड़ा हद्दसा हो जाए। पुरे शखों में कहें तो सरकारी तज जवानों के लिए बद्द हद्दसे की ईंज जार में रहता है। हले हुए हद्दसों से सबक सीखने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है। जिम्मेदारी का अभाव। यदि वह जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसी तरह के हद्दसे के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हद्दसा होने की सूत में उन्हें सख सजा मिलेगी, तभी हद्दसों पर लगाम लाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरुआत है। हर साल मानसून के दौरान देश में बाढ़ जनित हद्दसों में सैकड़ों लोगों की मौत होती है। भारी बारिश से देश को अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। जन-धन की इस हानि की किसी जिम्मेदारी तय नहीं है। आखिर क्यों हर साल होने वाले ऐसे हद्दसों के जिम्मेदारी हद्दसा है। हद्दसा होने के बाद सिर्फ लकीर पीटी जाती है। ऐसे उपाय नहीं किए जाते कि हद्दसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या फिर इनकी संख्या में कमी लाई जा सके।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी चल रही है, जो इतिहास में भारत का सबसे बड़ा साल रहा है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएँ अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई हैं, या दोनों ही बातें हो रही हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं, जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़, या सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013-2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार,



ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की संख्या ज्यादा है। सिसर रे एक प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और अध्ययन प्रकाशित करती है।

जून 2023 में, चक्रवात बिपरजाय ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ के सभी बंदरगाह, जैसे कांडवा और मुंद्रा बंदरगाह, बंद हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। दिसंबर 2023 में, चक्रवात मिफाऊं के चलते चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के

कारण बड़े नुकसान हुए। इसके अलावा, जुलाई 2023 में उत्तरी भारत, भारत और सिक्किम में आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। स्विस् रे के विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जड़ित हुआ है। इसका कारण भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत में गर्मी का मौसम (जून से सितंबर) और पर्वतारोहण

मॉनसून (अक्टूबर से दिसंबर) भारी बारिश लाते हैं, जिससे गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कुछ बड़ी घटनाओं में 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू और कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल की बाढ़ शामिल हैं। साल 2023 में उत्तर भारत की बाढ़ ने भी एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है कि नुकसान में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख है।

बहुते तापमान से चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं को तीव्रता और आवृत्ति बढ़ी है। इससे अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ता निर्माण और आबादी आपदा के समय अधिक नुकसान का कारण बनते हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं से सड़कों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। इससे ना केवल आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होती हैं बल्कि यह लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। कुदरती आपदाओं के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरी का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और फिर से निर्माण में भारी खर्च आता है। प्राकृतिक आपदाओं से भारत के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। तटीय राज्य, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल अक्सर चक्रवात और समुद्री तूफानों का सामना करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गांधी के मैदान हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

हैं। राजस्थान और गुजरात बार-बार सूखे का सामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी क्षेत्र भूकंप और भूखलन के लिए संवेदनशील हैं। साथ ही, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहर बाढ़ और जलमयता के लिए अधिक संवेदनशील हैं। वर्ष 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ भारत की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से हैं। इससे क्रमशः 5.3 अरब डॉलर और 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट कहती है कि इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बेहतर योजना और आपदा प्रबंधन की सख्त जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। स्विस रे के मुताबिक भारत को अक्षय पृष्ठधन और तैयारी के लिए बेहतर काम करना होगा और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो आपदाओं का सामना कर सके। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्विस रे की रिपोर्ट में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। जैसे कि डेटा और प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सर्वेक्षणशील क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा बनाना होगा। आधुनिक तकनीकों और डेटा का इस्तेमाल कर नुकसान का सर्वेक्षण आकरन किया जाए। ऐसी बीमा योजनाएं तैयार की जाएं, जो अधिक लोग तक पहुंच सकें और प्राकृतिक आपदाओं के बाद वित्तीय सुस्था प्रदान कर सकें। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में एक हिमनद के फटने के कारण बर्फ, हिम और मलबे का स्थलन होने से व्यापक 'फ्लेश फ्लड' उत्पन्न हुआ। भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति के रूप में 1,805 करोड़ रुपये मूल्य की हानि का कारण बनती है। सवाल यह है कि आखिर देश के लोग बाह्यजनित आपदाओं की मार कब तक झेलते रहेंगे। हर साल होने वाली मौतें और हजारों करोड़ की सम्पत्ति की बर्बादी आखिर कब थामेगी। सिर्फ प्रकृति को दोष से देने से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लापरवाही की बजानेबाजी का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा, जब तक सजा का कठोर प्राधान्य नहीं होगा। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

कोटपा एक्ट के तहत स्कूल के पास संचालित पाज गुटखा दुकानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई

बिलासपुर। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर सिरगिट्टी क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की। उन्होंने करीब एक दर्जन दुकानों में दबिश देकर उनका चालान काटकर जुर्माना वसूल किया। सीएमएचओ के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्रवाई अभियान में सुनील पंडा, औषधि निरीक्षक, श्रीमती सोनम जैन एवं सिरगिट्टी थाना प्रभारी के संयुक्त दल द्वारा सिरगिट्टी बनाक चौक, शासकीय प्राथमिक शाला सिरगिट्टी, शासकीय मिडिल स्कूल सिरगिट्टी, शासकीय कन्या शाला मिडिल स्कूल, सिरगिट्टी एवं सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल, सिरगिट्टी बिलासपुर के आस पास स्थित कुल 10 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन अनुरूप कुल छह सौ रुपए की चालानी कार्रवाई की गई । धारा 6 अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ को बिस्की नहीं होनी चाहिए। आज की कार्रवाई में स्थित ऐसी 09 दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं होना चाहिए । सिरगिट्टी क्षेत्र में स्थित ऐसी 01 दुकान जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे,उन्हें धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है, ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने हेतु कहा गया है।

मंत्रिपरिषद् का बड़ा निर्णय नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब अन्य विभागों में भी अनुकम्पा नियुक्ति का विकल्प

बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने एकजाई पुनर्रक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णक पारित हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।

श्रमिकों परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति योजना

बिलासपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ अर्थगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत समस्त पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसमें प्रमुख रूप से श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को हर कक्षा व पाठ्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना संचालित है। जिसमें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अध्ययनरत्न छात्र, छात्रा हेतु कक्षा-1 से पी0एच0डी स्तर तक अध्ययन करने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 हजार से 10 हजार तक प्रदान की जाती है एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत अध्ययनरत्न छात्र/छात्रा हेतु कक्षा 10वी, 12वी एवं स्नातक एवं उच्च शिक्षा में प्राांक 75 प्रतिशत अथवा अधिक हो को 5 हजार से साढ़े 12 हजार प्रदान किया जाता है। ।

न्यायालय तहसीलदार, बेमेतरा के न्यायालय मे मामला क्रमांक : 202506230600096	
मामले की श्रेणी:- राजस्व सन्- 2024-2025 विषय:- ब-121 बैजलपुर प.ह.न. 00039 [(हे०)] पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार -रामध्यान साहू, रामध्यान साहू, अनावेदक पक्षकार -	
ईश्टहार	
एतद सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामध्यान साहू पिता भगवती राम साहू निवासी ग्राम बैजलपुर तहसील व जिला बेमेतरा ने इस न्यायालय के समक्ष अपने दादी सोनबती पति हंसराम की मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है जिनकी मृत्यु दिनांक 05/07/1995 को स्थान ग्राम बैजलपुर में होना और भूलवश मृत्यु का पंजीयन नहीं करा पाना बताया गया है।	
उक्त आवेदन पत्र के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति को दावा/आपत्ति हो तो वे नियत पेशी तारीख 15/07/2025 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा किसी भी एक प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में इश्तहार का पेपर प्रकाशन हो।	
यह ईश्टहार मे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 30/06/2025 को जारी किया जाता है।	
तहसीलदार बेमेतरा	मुहर

आम सूचना	
मैं मेषराम चतुर्वेदी पिता मोहन दास चतुर्वेदी निवासी ग्राम ढारा पो. बावामोहतरा तहसील बेमेतरा जिला बेमेतरा छ.ग. का निवासी हूँ। यह कि मेरी पुत्री कि आधार कार्ड पर नाम थनेश्वरी एवं जन्म दिनांक 30/04/2011 दर्ज है। जबकी मेरी पुत्री कि जन्म प्रामण पत्र एवं मार्कशीट में नाम नंदनी चतुर्वेदी पिता मेषराम चतुर्वेदी जन्म दिनांक 05/06/2012 दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है। जिसके चलते समस्त शैक्षणिक दस्तावेज / शासकीय / अर्द्धशासकीय तथा अन्य समस्त दस्तावेज में जहा भी मेरी पुत्री कि नाम थनेश्वरी जन्म दिनांक 30/04/2011 दर्ज के स्थान पर शंशोधन कर नंदनी चतुर्वेदी पिता मेषराम चतुर्वेदी जन्म दिनांक 05/06/2012 दर्ज कराना चाहता हूँ। एवं उक्त नाम परिवर्तन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहता हूँ। अतः आज दिनांक 30/06/2025 से मेरी पुत्री कि समस्त दस्तावेज एवं आधार कार्ड पर मेरी पुत्री कि नाम नंदनी चतुर्वेदी जन्म दिनांक 05/06/2012 की प्रविष्टी करते हुए मेरी पुत्री को अब इसी नाम से जाना व पहचाना जावें।	
आवेदक मेषराम	मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार बेमेतरा, तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) ईश्टहार	
क्र./...प्र 1/तह./2025 रा.प्र.क. ब-121 वर्ष 2024-25	
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक लोभन सिंह वर्मा पिता उमेद सिंह वर्मा निवासी ग्राम करचुवा तहसील व जिला बेमेतरा द्वारा इस न्यायालय में अपने माता जी जनुकु बाई पति उमेद सिंह वर्मा के मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसका मृत्यु दिनांक 05/11/2024 को निवास साकिन में होना व भूलवश ग्राम/नगर पंचायत में मृत्यु का पंजीयन नहीं करा पाना बताया गया है।	
उक्त संबंध में जिस किसी को दावा/आपत्ति हो तो वे नियत पेशी तारीख 02/07/2025 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर अपनी दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	
आज दिनाँक 06/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर सहित ईश्टार जारी।	
नायब तहसीलदार बेमेतरा, जिला बेमेतरा	मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार बेमेतरा, तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) ईश्टहार	
क्र./...प्र 1/तह./2025 रा.प्र.क. ब-121 वर्ष 2024-25	
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक मोहन पिता गोफेलाल निवासी ग्राम भोथीडीह तहसील व जिला बेमेतरा द्वारा इस न्यायालय में अपने पत्नी पीला बाई पति गोफेलाल के मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसका मृत्यु दिनांक 05/03/2001 को निवास साकिन में होना व भूलवश ग्राम/नगर पंचायत में मृत्यु का पंजीयन नहीं करा पाना बताया गया है।	
उक्त संबंध में जिस किसी को दावा/आपत्ति हो तो वे नियत पेशी तारीख 02/07/2025 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर अपनी दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	
आज दिनाँक 18/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर सहित ईश्टहार जारी।	
नायब तहसीलदार बेमेतरा, जिला बेमेतरा	मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.) ईश्टहार	
क्र./...प्र 1/तह./2025 रा.प्र.क. अ-2 वर्ष 2024-25	
आवेदिका श्रीमती सरिता, पति संतोष, साकिन नवागढ़ तहसील नयागढ़ जिला बेमेतरा (छ.ग.) ने ग्राम नवागढ़, प.ह.नं. 13. तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 2462/23 का रकबा 0.06 हेक्टेयर को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।	
अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति पेश करना हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 07/07/2025 तक/पूर्व न्यायालय में पेश कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।	
आज दिनांक 27/06/002 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।	
अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़, जिला बेमेतरा	मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.) ईश्टहार	
क्र./...प्र 1/तह./2025 रा.प्र.क. अ-2 वर्ष 2024-25	
आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार, पिता रामसिंग साहू, साकिन ग्राम बदनारा, तहसील नांदघाट, जिला बेमेतरा (छ.ग.) ने ग्राम बदनारा, प.ह.नं. 05, तहसील नांदघाट, जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 407 का रकबा 1.45 हे. में से 0.40 हे. व 417/1 का रकबा 0.04 है. कुल रकबा 0.44 हेक्टेयर को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।	
अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति पेश करना हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 14/07/2025 तक/पूर्व न्यायालय में पेश कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।	
आज दिनांक 27/06/002 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।	
अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़, जिला बेमेतरा	मुहर

कलेक्टर ने बैठक में की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा

जिले के जर्जर स्कूल में क्लास नहीं लगाने के दिए निर्देश

- जन भागीदारी से 5 जुलाई को सामूहिक वृक्षारोपण
- अवैध प्लांटिंग की रजिस्ट्री पर लगाया प्रतिबंध

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में यदि एक भी स्कूल जर्जर हालात में है, तो उसमें क्लास नहीं लगने चाहिए। उन्होंने ऐसे स्कूलों की तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि मरम्मत के लिए राशि आवंटित की जा सके। कलेक्टर ने 5 जुलाई को आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सामाजिक भागीदारी से इस दिन हर आम और खास आदमी पौधे लगाएंगे। उन्होंने विभागवार जिम्मेदारी सौंपी। उनके द्वारा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने बैठक में अवैध प्लांटिंग को हतोत्साहित करने के लिए इसकी रजिस्ट्री पर रोक



लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बरसात के मौसम में जल संरक्षण और वृक्षारोपण के काम प्राथमिकता के साथ किये जाने हैं। सभी पौधे लगाएँ, किसी को पेड़ लगाने की मनाही नहीं है। एक पेड़ मां के नाम जारी अभियान के तहत बड़े आकार के पेड़ लगाया जाये। इसकी सुरक्षा करने में सुविधा होती है। कलेक्टर ने कहा कि पेड़ लगाना तो सहज है, ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम इसे बचाने का है। इस अभियान में स्थानीय लोगों और ग्रामीणों को जोड़ा जाए तो वे

अपनापन महसूस कर इसकी सुरक्षा करेंगै। पूरा शहर हरियाली युक्त होने चाहिए। बिलासपुर शहर में छिटपुट वृक्षारोपण के अलावा बिरकोना एवं राजकिशोर नगर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जायेगा। दोनों स्थल मिलाकर लगभग 12 हजार पौधे लगाये जाएंगे। कलेक्टर ने दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र सहित सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है,

कलेक्टर-एसपी ने पशु प्रबंधन को लेकर ली अधिकारियों की बैठक...

■ पशुओं के कारण

हुआ हादसा तो मालिक को भी सह आरोपी बनाया जाएगा

■ खुले में मवेशी छोड़े तो देना होगा भारी जुर्माना



आरोपी बनाया जाएगा। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, जोन कमिश्नर और नगरपालिका अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग और टैफ़्टिक पुलिस उपस्थित थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बरसात में सड़कों पर मवेशियों के बैठ जाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सभी विभाग आपस में मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शहरों में ऐसे जगह चिह्नित करें, जहां मवेशी ज्यादा बैठे होते हैं। उन क्षेत्रों में लगातार गश्त कर उन्हें हटाएं। मवेशी मालिकों का पता लगाकर उनसे संपर्क करें और समझाइश दें कि मवेशी को अपनी निगरानी में रखें। खुले में न छोड़ें। एक सर्वे के अनुसार बिलासपुर में लगभग 4 हजार जानवर खुले में विचरण करते पाए गए हैं। मालिक के सामने नहीं आने पर इन्हें पशु आश्रय स्थलों में रखे जाएंगे। शहर और आसपास के ग्रामों में आधा दर्जन से ज्यादा आश्रय स्थल विकसित किए जाएंगे। शहर के मोपका, कोनी, गोकुलधाम, सहित रहूंगी, धौराभांडा, पाराघाट, लावर, काटाकोनी में पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे।

खनिज आधारित उद्योगों से राज्य के विकास को मिलेगी नई गति : खनिज सचिव पी. दयानंद

चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू

200 मिलियन टन से अधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की नीलामी के लिए प्री-बिड सम्मेलन में शामिल हुए निवेशक

मूक पत्रिका/ रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज के नए ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में आज नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों के लिए प्री-बिड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्री-बिड सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज संपदा को औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को



आकर्षित करना है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव एवं खनिज सचिव पी. दयानंद ने कहा कि हमें नई औद्योगिक नीति के अनुरूप खनिज क्षेत्र के विकास के साथ प्री-बिड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्री-बिड सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज संपदा को औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी ई-नीलामी राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना

के लिए भरपूर संभावनाएं हैं।

खनिज सचिव पी. दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है, जहां कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, लीथियम, कोबाल्ट तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे 28 से अधिक प्रमुख खनिजों की भरपूर उपलब्धता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 51 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है और आने वाले समय में इस संख्या को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया

कि विभाग द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न खनिज समूहों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसके साथ ही सोनाखान भवन में एक ड्रिल कोर लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, ताकि अन्वेषण की गुणवत्ता और सटीकता को सुदृढ़ किया जा सके।

खनिज सचिव दयानंद ने यह भी बताया कि डीजीएम द्वारा चयनित कुल 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है, जिनमें 4 चूना पत्थर, 2 लौह अयस्क और 3 बॉक्साइट ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों में उपलब्ध संसाधनों का वाणिज्यिक दोहन निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चूना पत्थर के 200 मिलियन टन से अधिक भंडार बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित हैं, जिनमें औसतन 42 प्रतिशत से अधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आंकी गई है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे इन ब्लॉकों को एक आकर्षक औद्योगिक अवसर के रूप में देखें और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग, पारदर्शिता

और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

खनिज विभाग के संचालक रजत बंसल ने ई-नीलामी प्रणाली की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निविदा पोर्टल पर सभी खनिज ब्लॉकों से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्रों में रेलवे और सड़क जैसे मजबूत आधारभूत ढांचे के साथ स्थानीय श्रमशक्ति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे उद्योगों की स्थापना सुगम और आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी। प्रति वर्ष 3-4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले उद्योगों की स्थापना की संभावना के साथ इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार सृजन होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक अमित धारवाड़कर, संयुक्त संचालक अनुराग दीवान, संजय कनकाने सहित विभिन्न निवेशक, औद्योगिक प्रतिनिधि, भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ तथा खनिज एवं उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होगी चैंपियनशिप विश्व एथलेक्स चैंपियनशिप में होगा नीरज-अरशद का मुकाबला

नीरज आजकल शानदार फॉर्म में चल रहे

नई दिल्ली। भारत के स्टार एथलीट भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेक्स चैंपियनशिप में उतरेगे। यहां इनका मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से हो सकता है। अरशद भी यहां भाग लेने वाले हैं। नीरज आजकल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का आंकड़ा पारी करने के बाद पेरिस डायमंड लीग में जीत दर्ज की। साथ ही ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक इवेंट भी वह पहले नंबर पर रहे हालांकि, पेरिस और ओस्ट्रावा में वह 90 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाए। अब नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता में खेलते हुए दिखेंगे। नीरज दोहा में और फिर ओरलैन जानुस कुसोसिन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में जुलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं पेरिस और ओस्ट्रावा में पहला स्थान हासिल किया। हालांकि, इन चारों टूर्नामेंट में पाकिस्तान के नदीम नहीं थे। नदीम ने इस सत्र में ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लिया



है वह फिलहाल पाकिस्तान में ट्रेनिंग में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने पिछले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया था जिसमें नीरज नहीं खेले थे। नदीम ने वहां

86.40 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। नदीम ने कहा है कि उनका पूरा ध्यान विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है। उन्होंने लाहौर में एक कार्यक्रम में कहा कि मेरा ध्यान विश्व

एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। वह जल्द ही अभ्यास के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं जहां एक माह अभ्यास करेंगे।



विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरेंगे अविनाश साबले

नई दिल्ली। भारतीय एथलीट अविनाश साबले अब पूरी तरह से फिट हैं और उनकी निगाहें सितंबर में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सहित आगामी प्रतियोगिताओं में स्टीपलचेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। एशियाई खेलों के स्टीपलचेज चैंपियन साबले अभी ऊटी में अभ्यास कर रहे हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के केंद्र में अभ्यास करने में लगे हैं। साबले ने कहा कि मेरे लिए पिछला साल कुछ खास नहीं रहा पर इस साल मैं डायमंड लीग में भाग ले रहा हूँ। जिसके लिए मेरी तैयारी अच्छी है। मेरा लक्ष्य अपना इससे अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत समय हासिल करना है। अभी अभ्यास के 15 दिन बचे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आठ मिनट के अपने सर्वश्रेष्ठ समय के करीब पहुंच जाऊंगा। साबले साल 2023 में एशियाई खेलों के बाद से ही पिंडली की चोट से परेशान रहे हैं। उन्होंने 2025 के अपने सत्र की शुरुआत जियामेन डायमंड लीग में आठ मिनट 22.59 सेकंड के समय के साथ की और इसके बाद शाओक्सिंग में 8'23.85 सेकंड का समय निकाला। साबले ने मई में साउथ कोरिया के गुमी में एशियाई चैंपियनशिप में 8'20.92 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण जीता था। साबले ने कहा कि इस बार मेरी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। मैं सत्र की शुरुआत में चोटिल हो गया था पर इसके



बाद भी मैंने चीन में दो डायमंड लीग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। एशियाई चैंपियनशिप में भाग लेने से मेरा मनोबल बढ़ा है। जिसका लाभ मुझे मिलने की उम्मीद

भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में शामिल हुए स्पिनर हरप्रीत



बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो

लंदन। इंग्लैंड के खिलाफ 2 जुलाई से होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच से पहले बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बरार एजबेस्टन में टीम इंडिया के साथ अभ्यास करते दिखे। भारतीय टीम के पास पहले से ही रविन्द्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर हैं, ऐसे में हरप्रीत के यहां पहुंचने से सभी लोग हैरान रह गये। हरप्रीत भारतीय दल और भारत ए में भी शामिल नहीं थे। उसके बाद भी वह भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में दिखे तो सवाल उठना तया था। वहीं भारतीय बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया पर हरप्रीत के भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में पहुंचने का एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें हरप्रीत ने कहा है कि वह नये कप्तान शुभमन गिल के कहने पर टीम इंडिया के अभ्यास सत्र में शामिल हुए। बरार ने कहा कि उनकी पत्नी बर्मिंघम के करीब रहती है। जिसके पास वह पहुंचे थे तभी शुभमन ने उन्हें मैसेज कर अभ्यास के लिए बुलाया। बरार के अलावा, चंडीगढ़ के युवा तेज गेंदबाज जगजीत सिंह संधू भी गेस्ट गेंदबाज के रूप में नेट अभ्यास में जुड़े। पांच टेस्ट मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से पीछे हैं। ऐसे में 2 जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के लिए टीम अभ्यास में लगी हुई है। इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम देखकर उनकी जगह अर्शदीप सिंह को अवसर मिल सकता है। इसके अलावा शार्दूल ठाकुर की जगह आकाशदीप सिंह को जगह मिलेगी।

भारतीय टीम ने टी20 विश्वकप जीत के एक साल पूरा होने पर जश्न मनाया

बीसीसीआई ने पार्टी का वीडियो भी सोशल मीडिया में जारी किया

लंदन। भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2024 की जीत के एक साल पूरे होने पर रविवार को यहां एक पार्टी आयोजित की। इसमें केक काटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मजाकिया अंदाज में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की खिंचाई करने का प्रयास किया पर उन्हें करारा जवाब मिला। जडेजा ने कहा कि वह अभी एक फॉर्मेट से रिटायर हुए हैं। टी20 विश्व कप जीतने के बाद जडेजा ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। बीसीसीआई ने इस पार्टी का वीडियो भी सोशल मीडिया में जारी किया है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि पहले कोई भी खिलाड़ी केक काटने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी



अर्शदीप सिंह आगे बढ़े तो कहा गया कि बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, तो ऐसे में अर्शदीप की जगह बुमराह ने केक काटा। इसके बाद सभी खिलाड़ी एक दूसरे को केक खिलाने लगे।

वीडियो में बुमराह और ऋषभ ने जडेजा को 'हैप्पी रिटायरमेंट' कहकर केक खिलाया। इसपर जडेजा सफाई देते नजर आ रहे हैं उन्होंने अभी केवल एक ही प्रारूप से संन्यास लिया है।

डब्ल्यूटीसी अब अहमदाबाद में होना चाहिये : शास्त्री

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि अगला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (डब्ल्यूटीसी) फाइनल भारत के अहमदाबाद में होना चाहिये। शास्त्री के अनुसार इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए इंग्लैंड एक आदर्श स्थल है पर मेरा मानना है कि अब जब ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो गया है तो इसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्टेडियमों में भी किया जा सकता है। शास्त्री के अनुसार इंग्लैंड ने तीन बार इस टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी कर ली है। पहला डब्ल्यूटीसी फाइनल साउथैम्प्टन के रोज बाउल में आयोजित



किया गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। इसके बाद के दूसरा फाइनल ओवल में हुआ जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर चैंपियन बना। वहीं तीसरा फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। शास्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि शुरुआत में इसका लॉर्ड्स में आयोजन अच्छा है पर लोकप्रियता और प्रशंसा

मिलने के बाद इसे अन्य जगहों पर भी आयोजित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसके फाइनल के लिए अहमदाबाद स्टेडियम भी अच्छा रहेगा। उन्होंने साथ ही कहा, मूल रूप से, ऐसी जगहें जहां आप भीड़ खींच सकते हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अच्छी हैं लॉर्ड्स 100,000 सीटों वाला स्टेडियम नहीं है। इसलिए चाहे कोई भी टीम खेल रही हो, आपको पता है कि आपको अच्छी भीड़ मिलेगी, इसलिए स्टेडियम बदलना ठीक रहेगा। गौरतलब है कि साल 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक की मेजबानी इंग्लैंड के पास है, वहीं भारतीय बोर्ड ने 2027 फाइनल के लिए बोली लगाई थी पर उसे ये नहीं मिली।

आईसीसी ने इंग्लैंड महिला टीम पर जुर्माना लगाया



लंदन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम पर भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया है। इस प्रकार इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम को दोहरा झटका लगा है। इस मैच में उसे भारतीय टीम ने 97 रनों से हराया था। वहीं अब उसपर मैच फीस का 10 फीसदी जुर्माना लगा है। आईसीसी के अनुसार इंग्लैंड की टीम तय समय में पूरे 20 ओवर नहीं फेंक पाई थी। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय पैनल की मैच रेफरी हेलेन पैक ने इंग्लैंड टीम पर यह जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने इसी को लेकर कहा, खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायक कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के न्यूनतम ओवर-रेट संबंधी नियम के तहत ही खिलाड़ियों पर तय समय में गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच फीसदी जुर्माना लगाया जाता है।

इस मामले में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने सुझाई गई सजा को स्वीकार कर लिया इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आरोप चौथे अंपायर अन्ना हैरिस, तीसरे अंपायर सू रेडफर्न और मैदानी अंपायर जेम्स मिडलब्रुक और जैकलीन विलियम्स ने लगाए थे।

यश से पहले भी कई क्रिकेटर्स पर लगे हैं रेप के आरोप

मुम्बई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाये हैं। इस युवती का कहना है कि यश पिछले पांच साल से उसके साथ रिलेशनशिप में था पर अब उससे धोखेबाजी कर शादी से इंकार कर रहा है। अब इस मामले की जांच चल रही है।

ये पहला मामला नहीं है जब कोई क्रिकेटर इस प्रकार के गंभीर मामले में आरोपी है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स पर मारपीट और धोखेबाजी के आरोप लगते रहे हैं। अमित मिश्रा (भारत) पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा को एक महिला के आरोप के बाद बेंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमित पर दो धाराओं में मामला दर्ज किया गया था पर बाद में ये मामला भी दब गया। दानुष्का गुणाथिलका (श्रीलंका) श्रीलंका के बल्लेबाज दानुष्का गुणाथिलका को टी-20



विश्व कप 2022 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वह टीम से भी बाहर हो गये थे। गुणाथिलका पर टिंडर डेट के बाद महिला पर उसके घर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। बाद में वह इस मामले में बरी हो गये थे सदीप लामिछाने (नेपाल) नेपाल के स्टार स्पिनर सदीप लामिछाने पर साल 2022 में एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था। इस आरोप लगने के बाद वह टीम से बाहर हो गए और

उन्हें जेल भी जाना पड़ा था हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गयी। मखाया एनतिनी (दक्षिण अफ्रीका) साल 1999 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलने वाले पहले अश्वेत क्रिकेटर और तेज गेंदबाज मखाया एनतिनी पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था जिसके लिए उन्हें दोषी भी ठहराया गया। पर बाद में वह बरी कर दिये गये थे। रूबेल हुसैन (बांग्लादेश) 2015 को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रूबेल हुसैन को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उनकी पूर्व प्रेमिका और बांग्लादेशी अभिनेत्री नाजनीन अख्तर हैप्पी ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था पर बाद में अदालत ने रूबेल से मुक्त कर दिया है। रूबेल का कहना था कि नाजनीन उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी।

